

03 अब लगातार करेंगे, AAP के पाप का पर्दाफाश - अजय माकन

06 दवा बाजार में एंटीबायोटिक की अप्रभावीता

08 श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर एवं नंदिशाला का शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न

दिल्ली में वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन आयुक्त के द्वारा एक निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए आदेश से दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन मालिकों को अपने वाहनों के जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही दुर्लभ हो गया है तो वाहन जांच प्रमाण पत्र कहा से प्राप्त करेंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन मालिकों को वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिया गया निर्देश राजनेताओं के दिए गए भरोसे की तरह ही निकला और लोलीपाप बन कर रह गया। वाहन मालिकों द्वारा परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी निर्देशानुसार अपने वाहनों की जांच प्रमाण पत्र की समाप्ति की सूचना विभाग को देने के बावजूद उन्हें ना तो अपॉइंटमेंट दी जा रही है और ना ही ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। परिवहन आयुक्त भली भांति जानते हैं की आनलाइन साइबर कैफे वाले किस तरह आज वाहन मालिकों से वाहन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पर लूट खसोट का धंधा बना कर लूट रहे हैं और इस तरह के साइबर अपराध करवाने का मुख्य सूत्र स्वयं



परिवहन आयुक्त हैं यह लूट सिर्फ वाहन जांच प्रमाण पत्र के लिए लेने के लिए अनिवायं अपॉइंटमेंट तक ही सीमित नहीं है परिवहन आयुक्त की मेहरबानी के बदौलत जंपिंग नंबर लेने के लिए भी साइबर कैफे वाले और खास तौर से दिल्ली परिवहन विभाग

द्वारा ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर दिल्ली में नए वाहन बेचने वाले वाहन डीलर लूट खसोट में शामिल हैं।

टोलवा अध्यक्ष दिल्ली परिवहन आयुक्त को खुला चेलेंज देते हैं की कोई भी चाँडस का जंपिंग नंबर नई वाहन सीरीज

खुलने के साथ ही आनलाइन प्रक्रिया से लेकर दिखा दे, जब की परिवहन आयुक्त की कृपा प्राप्त वाहन डीलर वही चाँडस नंबर 100% गारंटी के साथ वाहन पर उपलब्ध कर देगा अपने विशेष शुल्क को प्राप्त कर।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

फुल ड्रेस रिहर्सल पर एडवाइजरी जारी बसों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों को लेकर आया अपडेट

गणतंत्र दिवस 2025 की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी को होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड रूट और यातायात व्यवस्था की जानकारी दी है। बसों और अंतरराज्यीय बसों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी चाहिए। लेख के माध्यम से पढ़िए 23 जनवरी के दिन यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी?



फुल ड्रेस रिहर्सल परेड यातायात निर्देश

4. दिल्ली सचिवालय / आईजी स्टैडियम
5. प्रगति मैदान मैरौ रोड
6. हनुमान मंदिर, यमुना बाजार
7. मोरी गेट
8. आईएसबीटी कश्मीरी गेट
9. आईएसबीटी सराय काले खां
10. तीस हजारी कोर्ट अंतरराज्यीय बस

गाजियाबाद से शिवाजी स्टैडियम जाने वाली बसें NH-24, रिंग रोड से होकर मैरौ रोड पर समाप्त होंगी। एनएच-24 से आने वाली बसें रोड नं.58 पर दाहिनी ओर मुड़ेंगी और आईएसबीटी आनंदविहार पर समाप्त होंगी।

गाजियाबाद की ओर से आने वाली बसों को मोहन नगर से वजीरबाद ब्रिज के लिए भोपराचुंगी की ओर मोड़ दिया जाएगा। धौलाकुआं की ओर से आने वाली सभी अंतरराज्यीय बसें धौलाकुआं पर समाप्त हो जाएंगी।

मेट्रो सेवाएं 23 जनवरी, 2025 को फुल ड्रेस

रिहर्सल समारोह के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध रहेगी।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दक्षिणी दिल्ली से - रिंग रोड - आश्रम चौक-सराय काले खां - रिंग रोड - राजघाट - रिंग रोड - चौक यमुना बाजार - एस.पी. मुखर्जी मार्ग - छत्ता रेल - कोडिया ब्रिज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें। हालांकि उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और संभावित देरी से बचने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर चलें।

एचटीवी/एनजीवी 22 जनवरी को रात 9 बजे 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल समाप्त होने तक किसी भी HTV/MGV/LGV को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)। इन वाणिज्यिक वाहनों को आगे की यात्रा के लिए दिल्ली की निम्नलिखित अंतर-राज्यीय सीमाओं से डायवर्ट किया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। साथियों वर्तमान दिल्ली सरकार से 12 वर्ष पूर्व डीटीसी की क्या स्थिति थी और आज 12 वर्षों बाद डीटीसी को वर्तमान दिल्ली सरकार की नीतियों ने कहां पहुंचा दिया है यह आपके सम्मुख कुछ बिंदुओं के माध्यम से रखने का प्रयास है कृपया ध्यान दें और 5 वर्षों के बाद आने वाले मताधिकार का प्रयोग डीटीसी के हित में अवश्य करें। साथियों 12 वर्ष पूर्व डीटीसी में अपनी बसों का बेड़ा (एसी, नॉन एसी) लगभग 4800 का था। जो की आज 0 हो गया है।

डीटीसी में 12 वर्ष पूर्व 38 डिपो से बसें संचालित होती थीं तथा दो विश्व स्तरीय केंद्रीय कर्मशाला चल रही थी जो कि आज नाम मात्र के 27 डिपो वो भी केवल दो माह के लिए तथा दोनों विश्व स्तरीय केंद्रीय कर्मशाला समाप्त हो गई हैं।

12 वर्ष पूर्व डीटीसी में 33000 स्थाई कर्मचारी/ अधिकारी थे तथा मात्र 4000 अस्थायी संवाहक थे।

जो की आज मात्र 4300 स्थाई कर्मचारी तथा 23000 अनुबंधित कर्मचारी हैं।

12 वर्ष पूर्व मात्र दो क्लस्टर कंपनियों द्वारा 350 बसों को संचालित किया जा रहा था। जो कि अब 13 क्लस्टर



कंपनियों द्वारा लगभग 3000 बसों को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में अनुबंधित चालकों, संवाहकों को स्थाई करने के लिए बार-बार वादे किए गए।

किंतु एक भी कर्मचारी को स्थाई नहीं किया गया।

डीटीसी से सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को वर्ष 2023 में लगातार अनियमित रूप से पेंशन दी गई एक समय तो ऐसा था जब 6 माह की पेंशन लंबित हो गई डीटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा बड़े-बड़े आंदोलन करने के बाद 6 माह की पेंशन का फरवरी 2024 में

भुगतान हो पाया किंतु अब जबकि कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि हर माह की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान समय पर करना है इससे बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा पेंशन वितरण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

31/8/2022 को डीटीसी बोर्ड द्वारा दो प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें सभी पर कैंसलेशन में डिकल स्कीम लागू करना तथा सभी कर्मचारियों को डीटीसी पेंशन के तहत लाने का प्रस्ताव था।

किंतु वह भी अभी तक लंबित है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कैंसलेशन में डिकल स्कीम का लाभ न

मिलने के कारण अभी तक सैकड़ों साथी हमारे बीच से बिना इलाज के अपना जीवन गवा चुके हैं।

साथियों निवर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तालकटोरा स्टैडियम में हजारों की भीड़ में कहा था कि हम डीटीसी का बेड़ा बढ़ाकर डीटीसी को विश्व स्तरीय परिवहन व्यवस्था बनाएंगे।

किंतु उसके ठीक विपरीत बसों का बेड़ा बढ़ाना तो दूर क्लस्टर को बढ़ावा देकर डीटीसी को फ्री की रेडियों के भेंट चढ़कर आज समाप्त कर दिया है। डीटीसी के किसी भी डिपो यहां तक कि डीटीसी मुख्यालय में भी प्रयाप्त कर्मचारी, प्रयाप्त

फर्निचर और साफ सुधरे शौचालय तक नहीं है। सभी डिपो में सफाई कर्मचारी, यहां तक कि डाक्टर भी पार्ट टाइम जॉब के लिए रखे गए हैं। डीटीसी द्वारा संचालित अधिकतर बस रुटों पर बस शैंड तक नहीं है।

साथियों डीटीसी हित में आपसे अपील है कि जो भी राजनीतिक दल डीटीसी को पुनर्जीवित कर उसी मान सम्मान के साथ चलाने का वादा अपने घोषणा पत्र में करें कृपया उसी को अपना मतदान/समर्थन करें डीटीसी के वर्तमान सेवारत, सेवानिवृत्त पेंशनधारी, पेंशन रहित परिवार लगभग 50000 हैं, जो कि दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा पर

प्रभावशाली हैं।

कृपया अपनी शक्ति एवं एकता का परिचय दें तथा सभी उम्मीदवारों पर यह दबाव बनाएं की उनकी सरकार बनने पर वह डीटीसी का अस्तित्व फिर से बहाल करेगा तथा अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई करेगा।

धन्यवाद।

नोट वर्तमान सरकार के तो वादे पर भी भरोसा ना करें क्योंकि पीछे कई मामलों वादा खिलाफी कर चुकी है।

निवेदनः समस्त डीटीसी कर्मचारी पिपोटर् पत्रकार हंसराज

भुवनेश्वर से कटक तक मेट्रो ट्रेन, वीवीआईपी दौरे के कारण मेट्रो परियोजना की गति धीमी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: भुवनेश्वर से कटक तक मेट्रो ट्रेन चलेगी। बीजद सरकार ने 2024 के आम चुनाव से पहले राजधानी के लोगों को ऐसा सपना दिखाया है। बताया गया कि यह परियोजना यातायात की भीड़ से बचने तथा लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जा रही है। अतीत पर विचार किए बिना नई सरकार ने चुप्पी साध ली है और पुरानी सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है।

उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए पहले ही गहन बैठक की है और 2027 तक मेट्रो चालू करने का वादा किया है। हालांकि, 2025 तक काम उतनी प्रगति नहीं कर रहा है जितनी कि उम्मीद थी। कभी राष्ट्रपति का दौरा होता है तो कभी प्रधानमंत्री का। कभी-कभी हमें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए काम रोकना पड़ता है, तो कभी ओडिशा में उत्कृष्टता सम्मेलन के लिए। जनता मैदान में एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित होने के कारण वीवीआईपी की आवाजाही बंद रहती है, जिससे योजना के अनुसार कार्य आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है (दो महीने से मेट्रो परियोजना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। सड़क किनारे बने फुटपाथ को ध्वस्त किये जाने के कुछ दिन बाद उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा है। अक्टूबर में पटिया चौक से किट चौक तक फुटपाथ हटाकर सड़क को चौड़ा करने का



काम शुरू हुआ था। हालांकि, काम शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत कर दी गई है, क्योंकि वीवीआईपी मुख्य रूप से नंदनकानन चिड़ियाघर और कटक आने-जाने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं। उत्तर भुवनेश्वर को 24 घंटे जलापूर्ति प्रदान करने के लिए वाटको द्वारा चल रहा जल पाइप बिछाने का काम भी रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, बरंग से त्रिशूलिया तक सड़क विस्तारिकरण का काम भी रोक दिया गया है। नवंबर में शुरू होने वाला मेट्रो का काम इस 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर तीन

स्थानों पर 200 मीटर लंबे लोहे के बैरिरेड्स लगाकर रोक दिया गया है। यहां तक कि शिशु भवन चौक से बानीबिहार चौक तक चल रहा काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह सच है कि काम बंद होने से शहरवासी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। यदि एक दिन बारिश रुक जाए तो जलपूर्ति असंभव हो जाएगी, ऐसा लग रहा था, जैसे पानी काला हो गया हो। मेट्रो परियोजना के लिए शहर में लगभग 3,200 पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि वन विभाग ने पहले चरण में सड़क किनारे और बीच में 1,400 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें कोई

प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा, 1,800 अन्य पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई है। सेवानिवृत्त प्रशासक प्रमोद पटनायक ने कहा कि मेट्रो बनने का मतलब यह नहीं है कि यातायात समस्या हल हो जाएगी। मुख्य सड़क पर भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन आसपास की सड़कों पर भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि शहर में वाहनों की संख्या कैसे कम की जा सकती है। विकसित शहरों को व्यवसाय के स्थान के रूप में नामित किया गया है। लेकिन यहां आज तक ऐसा नहीं हुआ।

चंडीगढ़ शहर में मेट्रो अभी तक चालू नहीं हुई है, जिसे भुवनेश्वर के साथ विकसित किया जा रहा है। यह जांचने लायक है कि वे इतने बड़े शहर में परिवहन को कैसे सुविधाजनक बनाया में सक्षम रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारी राजधानी में मेट्रो परियोजना, जो सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे तक सीमित है, परिवहन और आर्थिक दृष्टिकोण से सुविधाजनक होगी।

हेरिटेज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में भुवनेश्वर में कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वीवीआईपी के लगातार दौरे के कारण कार्यस्थल पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए मेट्रो परियोजना दो महीने के लिए रोक दी गई है। वीवीआईपी दौरे कुछ कम होने के बाद काम फिर से शुरू हो जाएगा।

वाह गजब ! अब 'गन्ने के रस' से चलेंगे वाहन, इथेनॉल करेगा कमाल

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: भुवनेश्वर से कटक तक मेट्रो ट्रेन चलेगी। बीजद सरकार ने 2024 के आम चुनाव से पहले राजधानी के लोगों को ऐसा सपना दिखाया है। बताया गया कि यह परियोजना यातायात की भीड़ से बचने तथा लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जा रही है। अतीत पर विचार किए बिना नई सरकार ने चुप्पी साध ली है और पुरानी सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है।

उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए पहले ही गहन बैठक की है और 2027 तक मेट्रो चालू करने का वादा किया है। हालांकि, 2025 तक काम उतनी प्रगति नहीं कर रहा है जितनी कि उम्मीद थी। कभी-कभी हमें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए काम रोकना पड़ता है, तो कभी ओडिशा में उत्कृष्टता सम्मेलन के लिए। जनता मैदान में एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित होने के कारण वीवीआईपी की आवाजाही बंद रहती है, जिससे योजना के अनुसार कार्य आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है (दो महीने से मेट्रो परियोजना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। सड़क किनारे बने फुटपाथ को ध्वस्त किये

जाने के कुछ दिन बाद उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा है। अक्टूबर में पटिया चौक से किट चौक तक फुटपाथ हटाकर सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था। हालांकि, काम शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत कर दी गई है, क्योंकि वीवीआईपी मुख्य रूप से नंदनकानन चिड़ियाघर और कटक आने-जाने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं। उत्तर भुवनेश्वर को 24 घंटे जलापूर्ति प्रदान करने के लिए वाटको द्वारा चल रहा जल पाइप बिछाने का काम भी रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, बरंग से त्रिशूलिया तक सड़क विस्तारिकरण का काम भी रोक दिया गया है। नवंबर में शुरू होने वाला मेट्रो का काम इस 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर तीन स्थानों पर 200 मीटर लंबे लोहे के बैरिरेड्स लगाकर रोक दिया गया है। यह सच है कि शिशु भवन चौक से बानीबिहार चौक तक चल रहा काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह सच है कि काम बंद होने से शहरवासी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। यदि एक दिन बारिश रुक जाए तो स्थिति असंभव हो जाएगी, ऐसा लग रहा था, जैसे पानी काला हो गया हो। मेट्रो परियोजना के लिए शहर में

लगभग 3,200 पेड़ काटे जाएंगे।

हालांकि वन विभाग ने पहले चरण में सड़क किनारे और बीच में 1,400 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे अलावा, 1,800 अन्य पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई है।

सेवानिवृत्त प्रशासक प्रमोद पटनायक ने कहा कि मेट्रो बनने का मतलब यह नहीं है कि यातायात समस्या हल हो जाएगी। मुख्य सड़क पर भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन आसपास की सड़कों पर भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि शहर में वाहनों की संख्या कैसे कम की जा सकती है। विकसित शहरों को व्यवसाय के साथ विकसित किया जा रहा है। लेकिन यहां आज तक ऐसा नहीं हुआ। चंडीगढ़ शहर में मेट्रो अभी तक चालू नहीं हुई है, जिसे भुवनेश्वर के साथ विकसित किया जा रहा है। यह जांचने लायक है कि वे इतने बड़े शहर में परिवहन को कैसे सुविधाजनक बनाया में सक्षम रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारी राजधानी में मेट्रो परियोजना, जो सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे तक सीमित है, परिवहन और आर्थिक दृष्टिकोण से सुविधाजनक होगी।

“देश के आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाएगा महाकुम्भ 2025” : राजेश खुराना

आगरा, संजय सागर सिंह | तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा महाकुम्भ 2025 न सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक बल्कि आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में भी अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने भी हाल ही में इसकी ओर संकेत किया था, जब उन्होंने कहा था कि महाकुम्भ से दो लाख करोड़ का व्यापार होगा। देश के महारू सीए, अर्थशास्त्री और अर्थ जानकारों की मानें तो 45 दिन तक चलने वाले महाकुम्भ से यूपी की जीडीपी में एक प्रतिशत या उससे भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है, जिससे राजस्व और जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस अहम आयोजन पर हमारे संवाददाता संजय सागर सिंह ने सीए, अर्थशास्त्री और अर्थ जानकारों की राय जानी जो इस प्रकार हैं -

अर्थ के जानकार, राजेश खुराना ने महाकुम्भ 2025 के आर्थिक प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन से 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उनका कहना है कि इस आयोजन के कारण नॉमिनल और रियल दोनों जीडीपी में एक प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि यदि महाकुम्भ में आने वाले करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं का औसत खर्च 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति माना जाए, तो इसका कुल कारोबार लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस राशि में कुछ रिस्क के चलते इसे चार लाख करोड़ रुपये मानते हुए भी यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

बसपा प्रत्याशी वकार चौधरी को अंसार नगर झुग्गी बस्ती, रमेश पार्क में मिला भारी समर्थन



सुषमा राणी

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वकार चौधरी को लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंसार नगर झुग्गी बस्ती, रमेश पार्क इलाके में अपने चुनावी दौरे के दौरान जबरदस्त समर्थन मिला। इस दौरान महिलाओं ने भी आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद दिया और स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं से वकार चौधरी को अवगत कराया।

वकार चौधरी ने निवासियों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वह चुनाव जीतते हैं, तो उनका सबसे पहला कदम क्षेत्र के सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना होगा। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना है।

जनसमर्थन से उत्साहित वकार चौधरी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की और विश्वास दिलाया कि जीत के बाद लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र बनेगा।

अस्थमा / दमा

अस्थमा (दमा) फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिस कारण श्वासन मार्ग सिकुड़ जाता है। श्वासन नली में सिकुड़ने के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न, खांसी आदि समस्याएं होने लगती हैं। लक्षणों के आधार अस्थमा के दो प्रकार होते हैं - बाहरी और आंतरिक अस्थमा।

बाहरी अस्थमा बाहरी एलर्जन के प्रति एक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है, जो कि पराग, जानवरों, धूल जैसे बाहरी एलर्जिक चीजों के कारण होता है।

आंतरिक अस्थमा कुछ रासायनिक तत्वों को श्वासन द्वारा शरीर में प्रवेश होने से होता है जैसे कि सिगरेट का धुआं, पेट वेपर्स आदि।

इस महाकुम्भ से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की जीडीपी में भी एक प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। श्री खुराना ने आगे कहा कि इस आयोजन से न केवल तिमाही आर्थिक आंकड़े मजबूत होंगे, बल्कि राष्ट्रीय वार्षिक जीडीपी में भी योगदान मिलेगा, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महाकुम्भ के माध्यम से राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को नया उत्साह मिलेगा और यह आयोजन देश के आर्थिक पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाएगा।

आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बनकर राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा महाकुम्भ 2025 : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने महाकुम्भ 2025 के आर्थिक पहलू पर अपनी बात रखते हुए कहा कि महाकुम्भ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी एक मोल का पत्थर साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हाल ही में इसकी ओर संकेत किया था कि महाकुम्भ से अनुमानित दो लाख करोड़ रुपये का व्यापार होगा, जो राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके चलते निवेश में वृद्धि, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। महाकुम्भ के आयोजन से भारतीय जीडीपी में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राजस्व और जीएसटी कलेक्शन

में अभूतपूर्व उछाल आ सकता है। श्री खान ने आगे कहा, यह आयोजन आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बनकर राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस प्रकार, महाकुम्भ 2025 न केवल धार्मिक आयोजन के रूप में बल्कि एक बड़े आर्थिक इजम के रूप में भी उभरने जा रहा है। कुल मिलाकर, महाकुम्भ 2025 आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बनकर राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के संकल्प को साकार करने की दिशा में सकारात्मक पहल साबित होगा।

महाकुम्भ 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम साबित होगा : संजीव कुमार सिंह

संजीव कुमार सिंह एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने महाकुम्भ 2025 के आयोजन को न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में भी महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हाल ही में कहा था कि महाकुम्भ से दो लाख करोड़ रुपये का व्यापार होने का अनुमान है। देश के प्रमुख सीए और अर्थशास्त्रियों के अनुसार, महाकुम्भ के 45 दिनों के आयोजन से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में एक प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। श्री सिंह ने आगे कहा, इस भव्य आयोजन से जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि वृत्तियभर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से मांग में वृद्धि होगी, जो उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। छोटे

से लेकर बड़े व्यापारियों की आमदनी में इजाफा होगा, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने अंत में कहा, इसके अलावा, सरकार को इस आयोजन से बड़ी आय प्राप्त होगी, जिसका उपयोग प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। इस प्रकार, महाकुम्भ 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम साबित होगा, जो वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम पहल होगी।

4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है कारोबार, अर्थव्यवस्था में जान डाल देगा महाकुम्भ 2025 : विजय पाल नरवार

विजय पाल नरवार के अनुसार, महाकुम्भ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ी सौगात साबित होगा। योगी सरकार ने महाकुम्भ को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। यह महाकुम्भ विश्व को इतने बड़े सफल कार्यक्रम के आयोजन का मंत्र भी सीखने का भी मौका देता है। प्रबंधन के विश्वस्तरीय संस्थानों को कुंभ से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई सतान रणनीति को सीखने का मौका देता है। इसका प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। इस भव्य आयोजन से प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु यहां पैसा खर्च करेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट, लोकल वेडर्स, दुकानदार, रिक्शा, टैक्सि और नाव सेवा प्रदाताओं

की आमदनी में भारी वृद्धि होगी। श्री नरवार का अनुमान है कि महाकुम्भ से लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है, और जो निवेश सरकार ने किया है, उसका दस गुना लाभ मिल सकता है। इससे सरकार को होने वाली आय का उपयोग विकास कार्यों में होगा, जिससे उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। श्री नरवार ने यह भी कहा, रमहाकुम्भ का असर सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहेगा; अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, और विन्ध्याचल जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों का आना-जाना बढ़ेगा, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश को जीएसटी कलेक्शन में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, और प्रदेश की जीडीपी में एक प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि की संभावना है। यह आयोजन न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि मांग और उत्पादन में वृद्धि के कारण एक मजबूत आर्थिक चक्र का निर्माण करेगा, जिससे राज्य की समग्र विकास प्रक्रिया को बल मिलेगा।

महाकुम्भ-2025 से बड़े पैमाने पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा : राजू शर्मा

राजू शर्मा ने कहा, रमहाकुम्भ - 2025 के भावनात्मक पहलू के साथ ही आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुम्भ - 2025 के अंतर्गत ही बनाएगा, इस आयोजन की भव्य व्यवस्था देश कर पूरी दुनियां दंग है, यहां देश विदेश से पहुंचा करोड़ों लोगों का जन सैलाब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना

हारा है। योगी महाराजजी की सरकार ने इस बार महाकुम्भ को लेकर जो निवेश किया है, उससे बड़े पैमाने पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इस भव्य आयोजन से न केवल भावनात्मक, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण लाभ होगा। सरकार ने इस बार महाकुम्भ के आयोजन पर जो निवेश किया है, उससे रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और भूमि आवंटन जैसे क्षेत्रों से व्यापक रेवेन्यू उत्पन्न होगा। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो जीएसटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। श्री शुक्लर ने आगे कहा, इस आय का इस्तेमाल जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में करेगी, तो इसका सकारात्मक असर समग्र अर्थव्यवस्था पर होगा। महाकुम्भ से टूरिज्म को भी विशेष बल मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग प्रयागराज आ रहे हैं। इस दौरान, प्रयागराज में 5 स्टार और 7 स्टार होटलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप, प्रदेश की जीडीपी में एक प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, जीएसटी कलेक्शन में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। यह भव्य आयोजन आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बनकर राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नया उत्साह मिलेगा और यह आयोजन देश के आर्थिक पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाएगा।

प्रवेश वर्मा ने पंजाबियों को गणतंत्र दिवस पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा कहा, क्या पंजाबी आतंकवादी और देशद्रोही हैं? : केजरीवाल

मुख्य संवाददाता सुषमा राणी

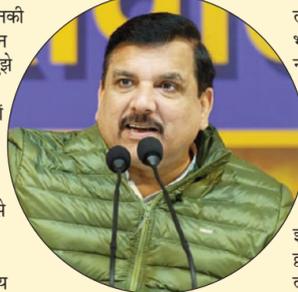
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा द्वारा दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियों में घूम रहे लोगों को गणतंत्र दिवस पर खतरा बताते हुए जाने पर तोखा पलटवार किया है। “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने सभी पंजाबियों का अपमान किया है। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पंजाबी गणतंत्र दिवस पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या सारे पंजाबी आतंकवादी और देशद्रोही हैं? दिल्ली में रह रहे लाखों पंजाबियों के परिवारों और उनके पूर्वजों ने देश के लिए आतंकवादी और देशद्रोही हैं? दिल्ली में रह रहे लाखों पंजाबियों के परिवारों और उनके पूर्वजों ने देश के लिए आतंकवादी और देशद्रोही हैं? दिल्ली में रह रहे लाखों पंजाबियों के परिवारों और उनके पूर्वजों ने देश के लिए आतंकवादी और देशद्रोही हैं?

गाड़ियों घूम रही हैं, पता नहीं उनमें कौन लोम है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए खतरा है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? क्या सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। आज जिस स्तर पर दिल्ली है, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। पंजाबियों के पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थीं। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान से लाखों रिफ्यूजी दिल्ली आए थे, उन्होंने ना जाने कितनी यातनाएं और दुर्दशा झेलीं। आज यह छोटा सा लड़का दिल्ली और पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह को पंजाबियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं, जिनके परिवारों और उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने

कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रिफ्यूजी भी रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ कर बसे थे। इनके परिवारों ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। भाजपा के नेता आज जो कह रहे हैं, इससे वो उनका शहादत और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। यह बयान सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। भाजपा को पंजाबियों से माफ़ी मांगनी चाहिए।

उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि मंगलवार को भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के अंदर पंजाब के नंबर प्लेट की गाड़ियों घूम रही हैं, जो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खतरा है। यह आरोप आम में बहुत गंभीर बात है। भाजपा के नेता सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। ये लोग शहीद-ए-आजम भगत सिंह के

वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करवाया। जिस समाज ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी कुर्बानियां दीं, ये लोग उसी



सिख समाज

को गालियां दे रहे हैं और उन्हें गणतंत्र दिवस के लिए खतरा बता रहे हैं।

संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में भाजपाइयों ने बांलादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, इन्हें उससे खतरा नहीं है। लेकिन अपने देश के ही एक हिस्से पंजाब की गाड़ियां अगर दिल्ली आ रही हैं, तो वह देश के लिए खतरा है। यह बहुत

शर्मनाक बयान है। यह पंजाबियों और सिखों की शहादत और देशभक्ति का अपमान है। बंटवारे के समय लाखों की संख्या में सिख और पंजाबी भाई दिल्ली आए। आज वो दिल्ली में रहते हैं और उनके लाखों रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं। भाजपा को आज ये लोग खतरा नजर न आ रहे हैं, जबकि इन्हें वो बांग्लादेशी घुसपैठियों खतरा नजर नहीं आते क्योंकि इनके दोस्त अडाणी का व्यापार उससे चल रहा है। और वो बांग्लादेश को हजारों करोड़ों रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है। इसलिए भाजपा नेता प्रवेश वर्मा द्वारा सिख और पंजाबी समाज को दी गई गाली का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी लोग 5 फरवरी को अपने वोट की ताकत से लेंगे

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, मंगलवार को नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया और थाने में बंद कर दिया गया। यह हर जगह हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहां हर राज्य के नंबर प्लेट की गाड़ियां होती हैं। दिल्ली के

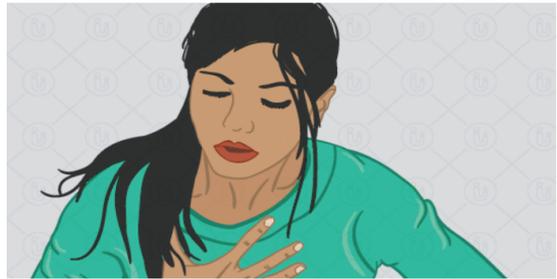
लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो प्रवेश वर्मा के इस बयान को न भूलें और इसे अपने दिलों-दिमाग में याद रखें। और 5 फरवरी को इस अपमान का बदला लें। यह भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए पूरे मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा भी शर्म है, तो वह प्रवेश वर्मा के बयान पर माफ़ी मांगें।

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आएंगे। क्या भाजपा ने दिल्ली को गुलाम बना लिया है? यहां हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे? क्या इसके लिए वो पहले प्रवेश वर्मा से इजाजत लेंगे? चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है और उन्हें थाने में भी बंद किया जा रहा है। खुले आम गुंडागर्दी चल रही है। प्रवेश वर्मा किस नियम के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को रोक लेंगे? क्या प्रवेश वर्मा चुनाव आयोग हैं? हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए आएंगे और कोई गुंडागर्दी करेगा तो हम कानूनी रूप से भी उसका जवाब देंगे।

आज हम आपको पुरानी खांसी सांस फूलना दमा जिसका खांसते खांसते पेशाब निकल जाता हो और मरीज की हालत बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती है डॉक्टर लोग उसको पंप देने की सलाह देते हैं पर यहाँ हम आपको उसके लिए एक बहुत बढ़िया योग दे रहे हैं,

इसको घर पर बनाकर रखें यह बड़ों से लेकर बच्चों तक बहुत ही कारगर दवा है आसानी से मिलने वाली दवाएं हैं जो बाजार से किसी भी पंसाड़ी की दुकान से मिल जाती।

1. काली मिर्च 50 ग्राम
2. सौंठ 50 ग्राम
3. काकड़ सिंगी 50 ग्राम
4. पोंकर मूल 50 ग्राम
5. कलौंजी 50 ग्राम



सब को अलग अलग कूट कर बाद में वजन करना है और अच्छी तरह से खरल करें और जंगली बेर के बराबर गोली बना ले और एक गोली सुबह एक गोली शाम अदरक के

रस में थोड़ा शहद मिलाकर उसके साथ दे 1 महीने में पूरी तरह आराम होगा और बाद में कभी भी दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

सभी सुखी और निरोगी रहे

अब लगातार करेंगे, ‘आप’ के पाप का पर्दाफाश : अजय माकन

सुषमा राणी

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, सांसद ने आप के पाप की सीरीज की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए अरविन्द केजरीवाल की फर्जीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। संवाददाता सम्मेलन को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने भी संबोधित किया। केग रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संग्रहण न है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र की केग रिपोर्ट के उजागर होने पर इसकी जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। उपराज्यपाल हस्तक्षेप करके इसकी जांच के आदेश दे।

संवाददाता सम्मेलन में 100 कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी सुखविंदर सिंह डैनी और दानिश अबरार, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डा. नरेन्द्र नाथ, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दूबे, कम्युनिस्ट विभाग के डा. अरुण अशवाल, ज्योति सिंह, रश्मि सिंह मिंगलानी, आरसा तस्लीम मौजूद थीं।

अजय माकन ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो

भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार में आए परंतु अपने और अपनी संरक्षक के भ्रष्टाचार की 14 केम रिपोर्ट कभी विधानसभा पटल पर सार्वजनिक नहीं होने दी। आज हम 14 रिपोर्ट में से एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके भ्रष्टाचार का खुलासा दिल्ली की जनता के सामने कर रहे हैं। केग रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 382.52 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि अरविन्द केजरीवाल यह बयान देते हैं कि हम समय से पहले और पैसे बचाकर काम पूरा करते हैं। केजरीवाल ने 10 वर्षों में सिर्फ 3

अस्पताल बनाए, जिनका काम की शुरुआत कांग्रेस शासन में हुई थी, कुल लागत में से 382.52 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल - पूरा होने में 5 साल की देरी हुई और 314.9 करोड़ अतिरिक्त खर्च

बुराई अस्पताल पूरा होने में 6 साल की देरी हुई व 41.26 करोड़ अतिरिक्त रुपये खर्च मौलाना आजाद डेंटल अस्पताल फेस-2 में 3 साल की देरी हुई और 27.36 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हुए। केजरीवाल सरकार ने 15 प्लाट अधिग्रहित किए जिन पर अस्पताल और डिस्पेंसरीय बननी थीं, मगर एक भी काम शुरू नहीं किया गया।

2016-2022 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर



प्रोजेक्ट का 2623.35 करोड़ लेम्प हो गया। कोविड महामारी में केन्द्र सरकार से मिले बजट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। केन्द्र सरकार से 635.62 करोड़ बजट मिला, जिसका 56.74 प्रतिशत 360.64 करोड़ खर्च ही नहीं किया। जबकि कोविड महामारी में लोग दवाई, आक्सीजन, बेड की कमी से दम तोड़ रहे थे।

2016-17 से 2020-21 चार वर्षों के बजट में 32000 बेड बनाने का लक्ष्य रखा लेकिन सिर्फ 3.86 प्रतिशत 1,235 बेड ही बढ़ा पाए। दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में बेड ओम्बेपूसी का औसत 101-189 प्रतिशत का है, मतलब एक बेड पर दो मरीज। 7 अस्पतालों में 109-160 प्रतिशत है।

चार अस्पताल- एलएनजेपी, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और जनकपुरी स्पेशलिटी मुख्यतः अस्पताल हैं, जिनमें केटी गैम और जांच की।

एलएनजेपी में मेजर बर्न सर्जरी का एक ऑपरेशन थिएटर है जो काम नहीं कर रहा। यहां ऑपरेशन के लिए 12 महीनों का वॉटिंग है। 12 ईसीजी मशीनों में से 5 काम ही नहीं कर रही हैं। चाचा नेहरू बच्चों का अस्पताल है यहां भी बच्चों की सर्जरी के लिए 12 महीनों का वॉटिंग है।

इन अस्पतालों में राजीव गांधी अस्पताल और जनकपुरी अस्पताल में 50-74 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी है, 73-96 प्रतिशत नर्सों की कमी है, 17-62 प्रतिशत पैरामेडिकल

स्टाफ की कमी है।

चाचा नेहरू अस्पताल में एक्सरे की प्रतिदिन क्षमता 330 है जिसमें 109 हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड 35 है 9 हो रहे हैं, सीटी स्कैन 12 - 3 हो रहे।

राजीव गांधी अस्पताल में एक्सरे की प्रतिदिन क्षमता 57 जिसमें 35 हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड 50 है 23 हो रहे हैं, सीटी स्कैन 26 - 14 हो रहे।

जनकपुरी अस्पताल में एक्सरे की प्रतिदिन क्षमता 57 जिसमें 24 हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड 30 है 1 हो रहा है। 27 अस्पतालों में से आईसीयू 14 में नहीं है, ब्लड बैंक 16 में नहीं है, आक्सीजन सुविधा 8 में नहीं, मोर्चुरी 15 में नहीं है और एम्बुलेंस सर्विस 12 अस्पतालों में नहीं है।

केट एम्बुलेंस में सुविधाओं का अभाव है - सिर्फ याव वाहन बन कर रहे हैं। केग द्वारा 4 अस्पतालों में जांच के बाद पाता चला कि सिर्फ एलएनजेपी के पास 2 एम्बुलेंस हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 21 प्रतिशत नर्सों की कमी है, कुछ अस्पतालों में कमी 34 प्रतिशत है।

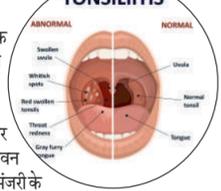
30 प्रतिशत कमी पॅरामेडिकल स्टॉफ की है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 30 प्रतिशत कमी है, और नर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 28 प्रतिशत की कमी है और मेडिकल अधिकारियों की 9 प्रतिशत की कमी है।

टॉन्सिल [Tonsils]

गले के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मांस की गांठें सी होती हैं जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। इनमें पैदा होने वाली सूजन को टॉन्सिलाइटिस कहा है। इसमें गले में बहुत दर्द होता है तथा खाने का स्वाद भी पता नहीं चलता है। चावल, ज़्यादा ठन्डे पेय पदार्थों का सेवन, मैदा तथा ज़्यादा खट्टी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना टॉन्सिल बढ़ने का मुख्य कारण है। इन सबसे अम्ल (गैस) बढ़ जाती है जिससे कब्ज हो जाती है। सदी लगने से, मौसम के अचानक बदल जाने से, जैसे गर्म से अचानक ठंडा हो जाना तथा दूधित वातावरण में रहने से भी कई बार टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। इस रोग के होते ही ठण्ड लगने के साथ खुबारा भी आ जाता है, गले पर दर्द के मरे हाथ नहीं रखा जाता और थूक नालाने में भी परेशानी होती है।

टॉन्सिलाइटिस के कुछ उपचार ---

1. गर्म (गुनगुने) पानी में एक चम्मच नमक डालकर गरम करने से गले की सूजन में काफी लाभ होता है।
2. दालचीनी को पीस कर चूर्ण बना लें। इसमें से चुटकी भर चूर्ण लेकर शहद में मिलाकर प्रतिदिन 3 बार चाटने से टॉन्सिल के रोग में सेवन करने से लाभ होता है। इसी प्रकार तुलसी की मंजरी के चूर्ण का उपयोग भी किया जा सकता है।
3. एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवायन डालकर उबाल लें। इस पानी को ठंडा करके उससे गरम और कुल्ला करने से टॉन्सिल में आराम मिलता है।
4. दो चुटकी पिप्पी हुई हल्दी, आधी चुटकी पिप्पी हुई काली मिर्च और एक चम्मच अदरक के रस को मिलाकर आठ गरम कर लें और फिर शहद में मिलाकर रोज़ को सोते समय लेने से दो दिन में ही टॉन्सिल की सूजन दूर हो जाती है।
5. गले में टॉन्सिल होने पर सिंघाड़े की पानी में उबालकर उसके पानी से कुल्ला करने से आराम होता है।
6. धोतन में बिना नमक की उबली हुई सब्जियाँ खाने से टॉन्सिल में जल्दी आराम आ जाता है।
7. मिर्च-मसाले, ज़्यादा तेल की सब्जी, खट्टी व ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।
8. गर्म पदार्थों के सेवन के पश्चात ठंडे पदार्थों का सेवन कदापि न करें।



गुरुग्राम में एमजीएफ बिल्डर की 82.29 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड की 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इस मामले में एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के निदेशक श्रवण गुप्ता द्वारा एम्मार इंडिया लिमिटेड के साथ 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और अवैध लेन-देन शामिल है।

नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली जिले ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड की 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 के तहत की गई है।

यह मामला एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के निदेशक श्रवण गुप्ता द्वारा एम्मार इंडिया लिमिटेड के साथ 180 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और अवैध लेन-देन से संबंधित है।

जब्त संपत्तियों में मेट्रोपालिटन मॉल का हिस्सा शामिल
जब्त संपत्तियों में गुरुग्राम के मेट्रोपालिटन

मॉल में करीब 50.83 करोड़ मूल्य का 42,364 वर्ग फुट का वाणिज्यिक परिया और दिल्ली के साकेत स्थित मेट्रोपालिटन मॉल में करीब 31.46 करोड़ का 33,601 वर्ग फुट का वाणिज्यिक परिया शामिल हैं।

ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की।

क्या है पूरा मामला ?

जांच में पता चला कि श्रवण गुप्ता ने एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड से करीब 180 करोड़ रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया। ईडी ने पाया कि गुरुग्राम सेक्टर 77 स्थित पाल्म हिल्स और सेक्टर 102 स्थित इंपीरियल गार्डन जैसे आवासीय प्रोजेक्ट्स के जरिए धन की हेराफेरी की गई।

जांच में शामिल नहीं हुए थे श्रवण गुप्ता
श्रवण गुप्ता ने एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड की ओर से नैनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट



लिमिटेड और सोम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नामक दो फर्जी कंपनियों को शामिल कर फर्जी और पुरानी तारीखों के समझौतों के माध्यम से धनराशि का दुरुपयोग किया।

जांच के दौरान ईडी ने श्रवण गुप्ता को कई बार समन जारी किया, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। ईडी ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

सोहना तहसील में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम बेरंग लौटी

सोहना तहसील परिसर में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अधिवक्ताओं के टीन शेट को हटाने गई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कुछ दिनों का समय मांगा, जिसके बाद इस कार्यवाही को टाल दिया।

तहसील का अपना न कोई भवन है न कोई कार्यालय, कई वर्षों तक हरियाणा परिवहन विभाग के बस स्टैंड के प्रथम तल पर तहसील कार्यालय था, लेकिन अगस्त में सोहना तहसील बस स्टैंड से पलवल बाईपास स्थित सिंचाई विभाग के रैस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अधिवक्ताओं ने नोटिस लेने से किया इनकार

सैकड़ों अधिवक्ताओं और नवशानवीसों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर कन्क्रीट डालकर टीन शेट बना लिए थे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सोहना बार को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन अधिवक्ताओं ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। सोमवार को उपायुक्त के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार की मौजूदगी में पुलिस बल और जैसीबी मशीन के साथ टीम मौके पर पहुंचे।

जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई बड़ी संख्या में अधिवक्ता इकट्ठे हो गए और उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से समय की मांग की। सिंचाई विभाग के एसडीओ सुरेश कुमार ने बताया कि टीन शेट बनने के समय से ही विभाग लगातार नोटिस दे रहा है। उन्होंने उपायुक्त से भी शिकायत की थी, लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा समय मांगे जाने के बाद फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई।

ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान में भी अग्रणी इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी विकास शर्मा ने लगवाए टीपी नगर में कैमरे



- अपराधियों की जल्द धर पकड़ में अहम भूमिका निभा रहा पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का ऑपरेशन त्रिनेत्र

सुनील बाजपेई कानपुर। यहां हर तरह के अपराधियों की धर पकड़ में पुलिस का सहयोग करने में अखिल हाई क्वालिटी के आईपी कैमरे लगवाने का सिलसिला यहां लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के इसी क्रम में अपराधियों के खिलाफ लगातार सफल मोर्चा खोले निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली के इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी की अगुवाई में बाबू पुरवा थाना क्षेत्र में भी अब तक लगभग 500 से अधिक

उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगवाए जा चुके हैं। इसी क्रम में हाल में ही इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर की तेजतर्रार और व्यवहार कुशल टीम चौकी प्रभारी विकास शर्मा द्वारा भी ट्रांसपोर्ट नगर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रात्र मधु फैक्ट्री से सामंजस्य स्थापित कर पॉपुलर धर्म कांटे को ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के क्रम में गोद लिया गया है, जिसके तहत अब ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में भी सीपी प्लस कंपनी के चार हाई क्वालिटी के आईपी कैमरे एस एण्ड पन कंप्यूटर कंपनी द्वारा लगवाए गये। अवगत कराते चलें कि यहां की पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब तक हजारों कैमरे लगवाई जा चुके हैं। और अब हाई क्वालिटी के यही कैमरे वारदात के बाद फरार होने वाले अपराधियों की अति शीघ्र धड़ पकड़ के मामले में बहुत अहम भूमिका निभाने में भी सफल हो रहे हैं। यह पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के लगातार जारी ऑपरेशन त्रिनेत्र का ही कमाल है कि वारदात के बाद फरार होने वाले सभी अपराधी पुलिस के शिकंजे में जल्द से जल्द फंसने से नहीं बच सके। यही नहीं आम जनता के जो भी लोग ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगवाने में पुलिस की सहायता कर रहे हैं। देश और समाज के लिए उनका यह सहयोग भी सराहना का पात्र है।

12 हजार बकायेदारों की खैर नहीं, संपत्ति कुर्क करेगा विभाग; एक्शन के लिए तैयारी पूरी

परिवहन विशेष न्यूज

बिजली बिल बकाया होने पर साहिबाबाद विद्युत विभाग ने 12 हजार बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और संपत्ति कुर्क की जाएगी। अभी तक 325 बकायेदारों का कनेक्शन काटकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जानिए आखिर विभाग की पूरी तैयारी क्या है ?

साहिबाबाद। बकायेदारों से राजस्व की वसूली नहीं होने से विद्युत निगम के अधिकारियों को मुख्यालय की कार्रवाई का डर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए 12 हजार बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

मुकदमा करा दिया दर्ज वहीं, 50 हजार से अधिक के इन बकायेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही संपत्ति कुर्क कर राजस्व की वसूली की जाएगी। निगम ने अब तक 325 का स्थायी रूप से कनेक्शन काटते हुए सेक्शन 138बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।

कड़ी कार्रवाई की तैयारी जिले में विद्युत निगम के तीनों जोन में वर्तमान में करीब 2.48 लाख बकाएदार हैं। इनमें से 50 हजार से अधिक के 12142 बकाएदार हैं। इन बकायेदारों पर कुल बकाए का करीब 80 प्रतिशत बकाया है। नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं होने पर निगम ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

जारी करेंगे कुर्की का नोटिस



बकायेदारों पर होगा एक्शन

स्थायी कनेक्शन काटने के साथ ही बकायेदारों पर वसुंधरा सेक्टर आठ के विलिन्स थाने में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके बाद शमन भेजकर बकाया जमा करने का समय दिया जाएगा। फिर भी बकाया जमा नहीं करने पर सभी अधिशासी अभियंता धारा-पांच के अंतर्गत रिक्वेरी चालान (आरसी) कुर्की का नोटिस जारी करेंगे। जिलाधिकारी और जिलाधिकारी (भू एवं राजस्व) को आदेश जारी करेंगे।

इसके बाद तहसील प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूली करेगा। दरअसल उम्मीद के अनुसार बकाया नहीं आने से परिचमाल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए लगातार फटकार लगाई जा रही है। विद्युत निगम का अभी ढाई लाख बकायेदारों पर करीब 350

करोड़ बकाया है। चार बार नोटिस किए जा चुके हैं जारी विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि बकायेदारों को अभी तक चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के दूसरे चरण में इक्का-दुक्का बकाएदार ही बकाए बिल की राशि जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी नोटिसों का बकायेदारों पर कोई असर नहीं हो रहा है।

छह अवर अभियंताओं को किया जा चुका निर्लंबित मुख्यालय के आदेश के बाद भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ बकायेदारों तक पहुंचाने में लापरवाही बरती जा रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए अब तक जौन-एक, दो व तीन के दो-दो अवर अभियंताओं को निर्लंबित किया जा चुका है। इसके बाद भी कुछ

खास राजस्व नहीं आया है। ओटीएस का तीसरा चरण आज से शुरू एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण 15 जनवरी को खत्म हो गया था। राजस्व की उम्मीद से मुख्यालय ने तिथि बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई थी। आज बृहस्पतिवार से योजना का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत बकायेदारों को ब्याज में अधिकतम 70 व न्यूनतम 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

50 हजार से एक लाख वाले कुल बकाएदार जौन -एक 525 जौन -दो 7471 जौन -तीन 576 एक लाख से अधिक वाले बकाएदार जौन -एक 322

ट्रंप के फैसलों से दुनियाँ दंग-बाइडेन के 78 फैसले भंग- क्या रुकेगी रूस यूक्रेन जंग ?

अवैध प्रवासियों, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने का स्वतःसंज्ञान अमेरिका की तर्ज पर भारत को भी लेना समय की मांग-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र गोंदिया - दुनियाँ का हर देश हैरत भरी नजरों से देख रहा है कि जिस तरह शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले ही संबोधन में दनादन फ़ैसलों की की घोषणा कर पदभार ग्रहण कर उनपर हस्ताक्षर भी कर दिए गए, जिसमें बाइडेन प्रशासन के 78 फ़ैसलों को तुरंत भंग कर दिया, टिकटक पर फिलहाल बैन पर रोक लगा, कनाडा मैक्सिको पर 25 पैसे टरिफ लगा दी, विश्व स्वास्थ्य संगठन व पेरिस जलवायु संगठन से बाहर होने की घोषणा की, जिसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा सहयोगी था जिससे उनकी वैश्विक योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना है। इन सबसे महत्वपूर्ण अब अवैध प्रवासियों की एंटी बंद करने के अलावा अब जन्मजात नागरिकता याने बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून को समाप्त करने को लेकर भी एजीक्यूटिव ऑर्डरेंस जारी कर दिए गए हैं, जिससे भारत सहित अनेक देशों पर फर्क पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हम नीचे पैरा में जिसकी चर्चा करेंगे। चूँकि अमेरिका में शपथ लेते ही ट्रंप का दे दनादन, पहले ही दिन 100 से अधिक महत्वपूर्ण फ़ैसले, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस ऑर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप के फ़ैसलों से दुनियाँ दंगी, बाइडेन प्रशासन के 78 फ़ैसले भंग, क्या रुकेगी रूस यूक्रेन जंग ? जन्मजात नागरिकता कानून भंग।

साथियों बात अगर हम ट्रंप द्वारा बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट को निरस्त करने की करें तो, अमेरिका में 150 साल से जन्मजात नागरिकता कानून अमेरिकी संविधान का 14 वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फ़ैसला

किया है। ट्रंप ने उन माता-पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। एच्यूसि सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। हालाँकि ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि यह केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के बाद अमेरिका में जन्मे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीय बच्चों की आने वाली पीढ़ी इसके दायरे में होगी। इसका मतलब ये है कि अब जिन लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता के वैध डॉक्यूमेंट नहीं हैं और इस दौरान अगर वे अमेरिका में अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उन बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश का नागरिकता संबंधी फ़ैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रवासी भारतीयों पर पड़ेगा। एच्यूसि की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका 48 लाख भारतीय मूल के निवासी बसे हुए हैं, इनमें से 16 लाख को जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है।

साथियों बात अगर हम बर्थराइट सिटीजनशिप एक्ट को समाप्त करने की चुनौतियों की करें तो, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी वैधता सवालों के घेरे में है। 114 वां संशोधन अमेरिकी संविधान का हिस्सा है, और इसके प्रावधानों को बदलने के लिए आम तौर पर एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो लंबी और कठिन होती है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश का उपयोग करके एक्टरफा रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त नहीं किया है। कानूनी विशेषज्ञ पहले से ही संघीय न्यायालयों में आदेश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स बनाम

वोग किम आर्क (1998) का ऐतिहासिक मामला भी शामिल है। इस मामले में न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया था कि गैर- नागरिक माता-पिता से यूएस में पैदा हुआ बच्चा अभी भी यूएस का नागरिक है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ तर्क यह है कि यह संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना संवैधानिक गारंटी को रद्द नहीं कर सकता है, जिसके लिए कांग्रेस में बहुमत और राज्यों में दो-तिहाई वोट की आवश्यकता होगी। फिर भी इस आदेश से कानूनी लड़ाई भड़कने की संभावना है जो सालों तक चल सकती है, जिससे प्रभावित लाखों लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

साथियों बात अगर हम अमेरिकी आबादि में भारतीय अमेरिकी समुदाय की करें तो, भारतीय-अमेरिकी समुदाय, जो अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अप्रवासी आबादी में से एक है, इस बदलाव से बहुत प्रभावित होगा। अमेरिकी जनगणना के अनुसार अमेरिका में 4.8 मिलियन से अधिक भारतीय- अमेरिकी रहते हैं। इनमें से लाखों जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर अमेरिकी नागरिकता रखता है। यदि नीति कार्यकारी आदेश के अनुसार बदलती है, तो अस्थायी बच्चे वीजा (जैसे एच -1बी वीजा) पर रहने वाले या ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब ऑटोमैटिक रूप से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इससे हर साल अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के हजारों बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। वर्तमान में भारतीय माता-पिता के अमेरिकी में जन्मे बच्चे, (चाहे वे एच -1बी वीजा पर हों, ग्रीन कार्ड पर हों या बिना किसी दस्तावेज के हों) को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती है। हालाँकि नए आदेश के तहत केवल कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को ही नागरिकता मिलेगी। यह उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो स्थायी निवास और अंततः खुद नागरिकता के लिए अपने बच्चों की नागरिकता की स्थिति पर निर्भर हैं। कई भारतीय माता-पिता,



विशेष रूप से एच-1बी वीजा पर काम करने वाले लोगों के लिए, अमेरिका में बच्चे का जन्म उनके बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का रास्ता है। जन्मसिद्ध नागरिकता के बिना, इन बच्चों को या तो खुद ही प्रक्रिया से गुजरना होगा या अपनी कानूनी स्थिति में अनिश्चितता का सामना करना होगा। भारतीय-अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यूएस ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसा हुआ है, जिसमें से कई लोग स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में एच -1बी या अन्य अस्थायी वीजा पर भारतीय नागरिकों के जन्मे बच्चे ऑटोमैटिक रूप से यूएस नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्हें परिपक्व होने पर अधिक सरल कानूनी विकल्प प्रदान करता है। यदि यह नीति रद्द कर दी जाती है, तो यूएस में भारतीय नागरिकों के जन्मे बच्चों को बहुत लंबी और अधिक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, इसके कारण यूएस नागरिकता प्राप्त करने के उनके मार्ग में कई साल और लग सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी वीजा पर यूएस में रहने वाले

भारतीय अप्रवासियों को अपने बच्चों के लिए निवास सुरक्षित करने का प्रयास करते समय अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में वर्क वीजा पर रहने वाले भारतीय अब अपने बच्चों को जन्म के समय अमेरिकी नागरिक बनते नहीं देख पाएंगे, इससे हर साल लाखों बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इससे ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वालों को और भी ज्यादा देरी का सामना करना पड़ सकता है। 110 लाख से ज्यादा भारतीय सालों से रोजगार से जुड़ा ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे हैं।

अतः अगर हम अपनी बहन का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के फ़ैसलों से दुनियाँ दंग-बाइडेन के 78 फ़ैसले भंग- क्या रुकेगी रूस यूक्रेन जंग ? - अमेरिकी बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून भंग। अमेरिका में शपथ लेते ही ट्रंप का दे दनादन- पहले ही दिन 100 से अधिक महत्वपूर्ण फ़ैसले। अवैध प्रवासियों, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने का स्वतः संज्ञान अमेरिका की तर्ज पर भारत को भी लेना समय की मांग।

ऑटो एक्सपो 2025 में यामाहा ने पेश की दो फ्यूल टैंक वाली बाइक, कई एडवांस फीचर्स से भी है लैस

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो 2025 में Yamaha ने Tenere 700 को पेश किया। इस बाइक में डबल फ्यूल टैंक दिया गया है। इसमें 689 cc CP2 पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इसे हार्ड और सॉफ्ट लगेज अपग्रेडेड रिकड प्लेट्स क्रैश बार्स और रैली सीट से लैस किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है। आइए जानते हैं कि Yamaha Tenere 700 किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

नई दिल्ली। ऑटो एक्सपो 2025 में

Yamaha ने एक ऐसी बाइक को पेश किया, जिसमें दो फ्यूल टैंक दिया गया है। यह बाइक न केवल डुअल फ्यूल टैंक के साथ आती है, बल्कि इसमें कई बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी बाइक सेगमेंट में डबल पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिला है। यामाहा की इस बाइक का नाम Tenere 700 है। यह बाइक बेहद शानदार है। आइए जानते हैं कि Yamaha Tenere 700 किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

इंजन

Tenere 700 में Yamaha का 689 cc CP2 पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल

किया गया है। इसके इंजन को MT-07 और XSR700 जैसे मॉडलों के साथ शेयर किया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 72 HP पावर और 68 NM टॉर्क जनरेट करता है।

एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम

इस बाइक में स्विचबल ABS (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) दिया गया है। इसकी वजह से ऑफ-रोड राइडिंग के दौरान राइडर को रियर व्हील का ABS बंद करने में आसानी रहती है। यह एक एडवेंचर बाइक है।

डबल फ्यूल टैंक

Yamaha ने Tenere 700 कई

बेहतरीन फीचर्स से लैस है। यह लोगों को अपनी तरफ ध्यान डबल फ्यूल टैंक की वजह से ज्यादा खींचती है। इसमें 23 लीटर की दो फ्यूल टैंक (Dual Fuel Tank Bike) का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल कैपैसिटी को और भी बढ़ा जाती है। इसमें हार्ड और सॉफ्ट लगेज, अपग्रेडेड रिकड प्लेट्स, क्रैश बार्स और रैली सीटें दी गई हैं। इसकी टॉप स्पीड 185 किमी प्रति घंटा है। वहीं, कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का माइलेज देती है। यामाहा इसे कई बेहतरीन एक्सेसरीज के साथ पेश करती है।

ऑफ-रोड राइडिंग के लिए बेस्ट

Tenere 700 ऑफ-रोड राइडिंग के लिए तैयार की गई है। इसमें 43 मिमी की पूरी तरह से एडजस्टेबल KYB फ्रंट फोर्क्स दिया गया है। वहीं, इसके फ्रंट में 200 मिमी ट्रेवल के साथ रिमोंट प्रोलोड एडजस्टेबिलिटी और रिबाउंड डंपिंग के साथ केवाईबी मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें 239 मिमी का ग्राउंड क्लियरेंस और 203 किलोग्राम कर्ब वेट है। इसमें 21 इंच का फ्रंट और 18 इंच का रियर व्हील दिया गया है, जो कठिन रास्तों पर आसानी से चलने में काफी मददगार होते हैं। बाइक में 62.8 इंच का व्हीलबेस दिया गया है।



देश के पहले सीएनजी स्कूटर टीवीएस जूपिटर में क्या है खास, कितनी होगी रेंज, कब तक हो सकता है लॉन्च, पढ़ें खबर

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो में टीवीएस जूपिटर सीएनजी स्कूटर 2025 भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता TVS Motors की ओर से Auto Expo 2025 में देश के पहले CNG Scooter के तौर पर TVS Jupiter CNG Scooter को शोकेस किया है। कंपनी की ओर से इस स्कूटर में किस तरह की खासियत को दिया गया है। कब तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में Bharat Mobility 2025 के तहत Auto Expo 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की प्रमुख दो पहिया निर्माता TVS Motors की ओर से पहले CNG Scooter के तौर पर TVS Jupiter CNG Scooter को शोकेस (India's First CNG Scooter) किया गया। कंपनी ने इसमें किस तरह की खासियत दी है। इसे कब तक और किस कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

शोकेस हुआ देश का पहला CNG Scooter TVS Jupiter

TVS मोटर्स की ओर से Auto Expo

2025 में देश के पहले CNG Scooter के तौर पर TVS Jupiter को शोकेस किया। इस स्कूटर में सीएनजी तकनीक के साथ ही कुछ और खासियतों को भी दिया गया है।

TVS Jupiter CNG Scooter

Engine

कंपनी की ओर से स्कूटर में 124.8 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है। जिससे स्कूटर को 5.3 किलोवाट की पावर और 9.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही स्कूटर को पेट्रोल और सीएनजी के साथ 226 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। स्कूटर के इंजन से इसे 80.5 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक चलाया जा सकता है और इसे एक किलोग्राम सीएनजी में 84 किलोमीटर तक चलाया (TVS scooter specifications) जा सकता है।

TVS Jupiter CNG Scooter

Features

टीवीएस की ओर से इसमें अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट दी गई है। इसके साथ ही इसमें मैक्स मेटल बॉडी, एक्सटरनल फ्यूल लिड, फ्रंट में मोबाइल चार्जर, सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर, बॉडी बैलेंस तकनीक, ज्यादा लेग स्पेस, इटीएआई तकनीक, इटैलीगो तकनीक, ऑल इन वन लॉक, साइड स्टैंड

इंडीकेटर के साथ इंजन इन्हिबिटर दिया गया है।

TVS Jupiter CNG Scooter

Expected Launch Time

कंपनी की ओर से अभी इसके लॉन्च को लेकर किसी भी तरह की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस स्कूटर को अगले तीन से छह महीनों के बीच लॉन्च (TVS Jupiter launch Date) किया जा सकता है।

TVS Jupiter CNG Scooter

Expected Price

TVS की ओर से अभी इस स्कूटर को सिर्फ शोकेस किया गया है। कुछ महीनों में जब इसे लॉन्च किया जाएगा तब इस स्कूटर की एक्स शुरुआत कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसकी संभावित एक्स शुरुआत कीमत एक लाख रुपये के आस-पास हो सकती है।

किनसे मिलेगी चुनौती

टीवीएस की ओर से सीएनजी तकनीक के साथ Jupiter CNG को लाया गया है। बाजार में यह पहला स्कूटर है जिसे सीएनजी तकनीक के साथ लाया गया है। ऐसे में इस स्कूटर का सीधा मुकाबला किसी भी स्कूटर के साथ नहीं होगा। लेकिन बाजार की सीएनजी बाइक से इसे चुनौती मिल सकती है।



इसुजु ने पेश किया डी-मैक्स ईवी कॉन्सेप्ट, सिंगल चार्ज में देगी 300 किमी तक की रेंज

ऑटो एक्सपो 2025 में इसुजु डी-मैक्स ईवी कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया गया। इसमें 66.9 kWh बैटरी पैक दी गई है जो 175 bhp की पावर और 325 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस बैटरी को दो मोटर से कनेक्ट किया गया है। इसमें लगी हुई बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 300 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकेगी।

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में Isuzu ने D-Max EV पिकअप ट्रक का इलेक्ट्रिक वर्शन D-Max EV कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि अभी तक उनका मॉडल डेवलपमेंट स्टेज पर है, इसे जल्द ही उत्पादन में लाया जा सकता है। इसमें बड़ी बैटरी के साथ ही ज्यादा रेंज मिलेगी। आइए जानते हैं कि Isuzu D-Max EV Concept किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आ सकती है।

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

Isuzu D-Max EV Concept में 66.9 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। यह बैटरी दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के जरिए पहियों तक पावर पहुंचाती है। एक मोटर हर एक्सल पर लगाया गया है। यह दोनों मोटर मिलकर 175 bhp की पावर और 325 Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि इस पिकअप ट्रक में लगी हुई बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 300 किमी तक की रेंज प्रदान कर सकता है। अभी



यह डेवलपमेंट स्टेज पर है तो यह रेंज 300 किमी की रेंज से ज्यादा हो सकती है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हो सकता है।

Isuzu D-Max EV Concept में 1,000 किलोग्राम का पेलोड कैपैसिटी और 3.5 टन तक की टोइंग कैपैसिटी दी गई है, जो इसे एक स्ट्रॉंग और फंक्शनल पिकअप बनाता है।

एक्सटोरियर

D-Max EV में ICE की तुलना में

बाहरी डिजाइन में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इस पिकअप ट्रक में नई ग्रिल दी गई है, जिसमें ब्लू इंसर्ट दिए गए हैं। फ्रंट और रियर बंपर को भी ट्यूबो किया गया है, जिसकी वजह से यह और भी स्टाइलिश नजर आती है। इसमें नया सेट एलॉय व्हील्स और रीडिजाइन हेडलाइट क्लस्टर भी शामिल किया गया है। ट्रक के टेल लाइट्स में भी बदलाव किए गए हैं, जो इसे और ज्यादा

प्रीमियम लुक देते हैं।

इंटीरियर

Isuzu के D-Max EV कॉन्सेप्ट मॉडल के इंटीरियर की ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बाहरी बदलावों के साथ ही अंदर में भी हल्के बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें नए अपहोल्स्ट्री और ब्लू इंसर्ट्स भी हो सकते हैं जैसा इसके बाहरी डिजाइन में देखने के लिए मिला है।

भारत मोबिलिटी 2025 का आज आखिरी दिन, ऑटो एक्सपो 2025 में लगा कारों और बाइक का मेला

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो 2025 दिल्ली के प्रगति मैदान के साथ ही द्वारका और ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया Bharat Mobility Global Expo 2025 का आज आखिरी दिन है।

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी

2025 का आज आखिरी दिन है। इसके तहत होने वाले Auto Expo 2025 में कितने प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से हिस्सा लिया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया। कहां कहां पर इसका आयोजन हुआ। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Bharat Mobility

2025 का आज आखिरी दिन

भारत मोबिलिटी 2025 का

आज आखिरी दिन है। इसके साथ

ही आयोजित किए जा रहे Auto

Expo 2025 का भी आज समापन

हो जाएगा। मोबिलिटी एक्सपो का

आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान के

साथ ही द्वारका और ग्रेटर नोएडा के

एक्सपो सेंटर में हो रहा है।

कब तक देख सकते हैं एक्सपो

भारत मोबिलिटी 2025 के

तहत आयोजित किए जा रहे Auto

Expo 2025 में आखिरी दिन भी

सुबह 10 बजे से कारों को देखा

जा सकता है। इस कार्यक्रम का समापन

शाम को छह बजे हो जाएगा।



कब शुरू हुआ था एक्सपो
Bharat Mobility 2025 का आयोजन 17 जनवरी 2025 से किया गया था। इसमें पहले दिन सिर्फ मीडिया के लिए रिजर्व रखा गया था। दूसरे दिन डीलर्स डे और मीडिया के लिए रिजर्व किया गया था। इसके बाद 19 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 के बीच इसे जनता के लिए खोल दिया गया था।

किन निर्माताओं ने लिया हिस्सा
Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए गए Auto Expo 2025 में देश और दुनिया की कई प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से हिस्सा लिया गया था। इस दौरान

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata, Mahindra, JSW MG, Mercedes Benz, BMW, BYD, Porsche, Skoda, Vinfast, Hero Motocorp, Honda Two Wheeler, Suzuki Two Wheeler, TVS, VECV, Ashok Leyland, Ola, Ather, Bajaj सहित कई प्रमुख वाहन निर्माताओं ने कई बेहतरीन उत्पादों को शोकेस किया और कई कारों और दो पहिया वाहनों को लॉन्च भी किया गया।

देश में Bharat Mobility Global Expo की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई थी। तब इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। जिसके बाद अब 2025 में भी इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2026 में भी इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा सकता है।

क्या है उद्देश्य
देश में Bharat Mobility Global Expo का आयोजन करने का उद्देश्य कॉन्सेप्ट के तौर पर भविष्य के वाहनों, तकनीक, डिजाइन की झलक को दिखाने के साथ ही नए वाहनों को पेश और लॉन्च करना है। जिसे जनता आसानी से देख सकती है।

मारुति ने शोकेस किए सात कारों और एसयूवी के संकल्पना संस्करण, स्विफ्ट से लेकर जिम्नी तक हैं शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति सुजुकी की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए जा रहे Auto Expo 2025 में कई बेहतरीन Cars and SUVs को शोकेस किया जा रहा है। इस दौरान कंपनी की ओर से कुछ मौजूदा कारों के Concept Version पेश किए गए हैं। जिनको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कंपनी ने किस गाड़ी का कौन सा वर्जन शोकेस किया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए जा रहे Auto Expo 2025 में कई बेहतरीन Cars and SUVs को दिखाया गया है। कंपनी ने कुछ मौजूदा कारों के Concept Version भी इस दौरान पेश किए हैं, जिनको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मारुति की ओर से किस गाड़ी को किस तरह के कॉन्सेप्ट वर्जन के साथ शोकेस किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Swift का Champions

Concept वर्जन पेश हुआ

Maruti की ओर से Hatchback सेगमेंट में Swift को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान इस गाड़ी के

Champions concept वर्जन को पेश किया है। इस वर्जन को सामान्य कार से अलग बनाने के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स का उपयोग बोनट, साइड प्रोफाइल पर किया गया है। साथ ही इसमें रियर स्पोयलर को भी जोड़ा गया है। गाड़ी के टायर्स पर भी सफेद रंग से हाइलाइट किया गया है। रियर में भी ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है।

Maruti Dzire का Urban Luxe

Edition किया शोकेस

कंपनी की ओर से नवंबर 2024 में लॉन्च की गई Dzire की नई जेनरेशन को भी Urban Luxe Edition के साथ शोकेस किया गया है। जिसमें कई पार्स पर क्रोम का उपयोग किया गया है। जिससे गाड़ी का लुक काफी प्रीमियम लगता है।

Maruti Grand Vitara का

Adventure Concept हुआ पेश

मिड साइड एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Maruti Grand Vitara को भी Adventure Concept के तौर पर शोकेस किया गया है। इसमें एसयूवी को लाइट ग्रीन रंग के साथ बेहतरीन ग्राफिक्स दिए गए हैं। रूफ पर रूफ रेल के साथ साइकिल को रखा गया है। वहीं साइड प्रोफाइल में गाड़ी पर 4X4 Allgrip के साथ पहाड़ों के ग्राफिक्स दिए गए हैं।

Maruti Jimny का Conqueror

concept हुआ शोकेस

कंपनी की ओर से ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर जिम्नी को ऑफर किया जाता है। Auto Expo 2025 के दौरान इस गाड़ी के Conqueror Concept को शोकेस किया गया है। जिसमें गाड़ी को रिंगस्तान की रेत जैसे रंग वाले एक्सटोरियर के साथ लाया गया है। इसके फ्रंट में दूसरी गाड़ी से टो करवाने के लिए सेट-अप दिया गया है और साइड प्रोफाइल में ब्लैक रंग के साथ जिम्नी और 4X4 को लिखा गया है। साइड प्रोफाइल के रियर में स्टैंड के साथ जैरी के लिए लगाई गई हैं और छत पर स्टैंड के साथ सामान रखने की जगह बनाई गई है।

Maruti Brezza का Powerplay

Concept हुआ पेश

मारुति की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली ब्रेजा का पावर प्ले कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया है। जिसमें क्रोम का उपयोग फ्रंट में किया गया है और साइड प्रोफाइल पर ब्लैक रंग के ग्राफिक्स के साथ सफेद रंग में ब्रेजा की बैजिंग दी गई है।

क्यों किए शोकेस

कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2025 में इन कारों के कॉन्सेप्ट को इसलिए शोकेस किया है, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें और अपनी कार के लुक को और बेहतर कर पाएं। कंपनी की ओर से यह सब एक्सेसरीज के तौर पर दिखाया गया है।



बजट में होगा सस्ते इलाज का उपाय? क्या है हेल्थ सेक्टर की वित्त मंत्री से उम्मीदें

परिवहन विशेष न्यूज

हेल्थ सेक्टर आगामी बजट में टैक्स सुधार की भी उम्मीद कर रहा है। इस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को शून्य करने या इसे 5 फीसदी वाले स्लैब में लाने की वकालत कर रहे हैं। इससे अस्पतालों और नर्सिंग होम की लागत में काफी कमी आ सकती है। हेल्थ सेक्टर अस्पतालों को बुनियादी ढांचे के निवेश के रूप में Reclassified करने की भी मांग कर रही है।

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। सरकार हेल्थ सेक्टर पर फोकस लगाता बढ़ा रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार बजट में हेल्थ जैसे प्रमुख सेक्टर के लिए आवंटन करीब 10 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, मेडिकल डिवाइसेज पर एक समान जीएसटी की भी मांग हो रही है। पिछले साल आम बजट में वित्त मंत्री ने हेल्थ के लिए 90,958 करोड़ रुपये दिए थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अनुमानों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा पर होने वाला खर्च 2013-14 में 64.2 फीसदी से घटकर 2021-22 में 39.4 फीसदी हो गया है, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसी अवधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यय जीडीपी के 1.13 फीसदी से बढ़कर 1.84 फीसदी हो गया है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि यह 2030 तक 3 फीसदी के लक्ष्य से बहुत दूर है।

हेल्थ सेक्टर के लिए रोडमैप की जरूरत
फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अशोक शर्मा ने कहा, 'हमें पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की उम्मीद है। रणनीतिक निवेश और सहायक नीतियों से

खाने के रिफाइंड तेल पर बढ़ाया जाए आयात शुल्क, उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्री से की अपील

बजट 2025 एप्रैल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि खाने के रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए। उद्योग संगठनों ने इस संबंध में वित्त मंत्री को बजट ज्ञापन भेजा है। एप्रैल में तैयार उत्पादों के शुल्क-मुक्त आयात पर प्रतिबंध की मांग की है। एप्रैल में कहा है कि रिफाइंड पाम तेल के आयात पर शुल्क को मौजूदा 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाए।

नई दिल्ली। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने सरकार से आगामी बजट में रिफाइंड खाद्य तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाने, साबुन और नूडल्स जैसे तैयार उत्पादों के शुल्क-मुक्त आयात पर प्रतिबंध लगाने और तेल रहित चावल की भूसी पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे बजट ज्ञापन में एसईए ने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल

ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटा जा सकता है और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के हर कोने तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है।

टैक्स में भी सुधार चाहता है सेक्टर
हेल्थ सेक्टर आगामी बजट में टैक्स सुधार की भी उम्मीद कर रहा है। इस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को शून्य करने या इसे 5 फीसदी वाले स्लैब में लाने की वकालत कर रहे हैं। इससे अस्पतालों और नर्सिंग होम की लागत में काफी कमी आ सकती है।

आकाश हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष चौधरी ने कहा, रनई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35AD के तहत 150 फीसदी कटौती को बहाल करना और नए प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम 15 साल के लिए टैक्स छूट देना, साथ ही मौजूदा सुविधाओं के लिए 10 साल की टैक्स राहत भी प्रमुख मांगों हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की मांग
हेल्थ सेक्टर अस्पतालों को बुनियादी ढांचे के निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत (Reclassified) करने की भी मांग कर रही है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने में आसानी हो सकती है। यह अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। चिकित्सा उपकरणों के लिए व्याज दर में छूट के साथ, ये सुधार भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

पीएसआरआई अस्पताल में डीजीएम फार्नेस अनूप मेहरा ने बताया, र अस्पतालों को बुनियादी ढांचे के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से दीर्घकालिक निवेश के रास्ते खुल सकते हैं,



जिससे इस क्षेत्र को क्षमता का विस्तार करने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलेगी।

आयुष्मान भारत के बारे में भी सुझाव
भारत के टियर II और टियर III शहर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के मामले में कम सेवा वाले हैं। हेल्थ इंडस्ट्री इन क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की तत्काल जरूरत पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-पीएमजेवाई योजना ने छोटे शहरों में मांग में वृद्धि की है। हालांकि, हेल्थ सेक्टर का दावा है कि इस योजना के मौजूदा मूल्य निर्धारण मॉडल सेवा वितरण की वास्तविकता को दर्शाते हैं। इससे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर वित्तीय रूप से मुश्किल में पड़ जाते हैं।

बानेर पुणे में जुपिटर अस्पताल के सीईओ डॉ. राजेंद्र पाटनकर ने कहा, र पैकेज मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाना और बिजली और उपयोगिताओं के लिए परिचालन सक्विटी प्रदान करना, जो सरकारी अस्पतालों को दी जाती है, इस बोझ को कम कर सकता है। न्यायसंगत मूल्य निर्धारण मॉडल और परिचालन लागत पर राहत के बिना, स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना



सेवा प्रदाता इन क्षेत्रों में परिचालन को बनाए नहीं रख सकते हैं, र।

एनसीडी से भारत को \$6 ट्रिलियन का नुकसान

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) में वृद्धि एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। 2030 तक, एनसीडी से भारत को \$6 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। इससे व्यापक जांच और निदान कार्यक्रम तत्काल प्राथमिकता बन गए हैं। सिटी एक्स-रे के सीईओ डॉ. आकार कपूर ने इन कार्यक्रमों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 'जल्दी पता लगाने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा लागत कम हो सकती है और रोगी के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए क्लूट और उपकरणों पर कम आयात शुल्क जैसे प्रोत्साहन आवश्यक हैं।'

भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) की भी जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा नीतियां इस उभरते क्षेत्र का पूरा समर्थन नहीं करती हैं। एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ. एन. के. पांडे ने जोर देकर कहा, र मेडिकल टूरिज्म से होने वाली आय पर क्लूट और अंतरराष्ट्रीय मरीजों के लिए



वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने से भारत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र बन सकता है। भारत की चिकित्सा विशेषज्ञता और लागत लाभ बेजोड़ हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आकर्षित करने के लिए मेडिकल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे स्वास्थ्य सेवा-विशिष्ट व्यवसाय ट्रस्टों के निर्माण जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र की सलाह देते हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा, 'अनुकूलित फंडिंग तंत्र नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और हमारी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर सकते हैं।'

इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में फंडिंग की दिक्कत

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में फंडिंग एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। विशेषज्ञ 'फंड ऑफ फंड्स', सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे स्वास्थ्य सेवा-विशिष्ट व्यवसाय ट्रस्टों के निर्माण जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र की सलाह देते हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा, 'अनुकूलित फंडिंग तंत्र नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और हमारी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर सकते हैं।'

यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं की तीव्र कमी को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता भी चाहता है। जबकि 70 फीसदी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है, 80

फीसदी विशेषज्ञ शहरी केंद्रों में केंद्रित है। यह असमानता, छोटे शहरों में उन्नत चिकित्सा उपकरणों की कमी के साथ मिलकर, गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। इस अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। अनूप मेहरा, के अनुसार, 'सरकार को कम सेवा वाले क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और व्यापक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन बनाना चाहिए।'

बीमा सुधारों की भी है जरूरत
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी और विशेषज्ञों ने बीमा सुधारों के महत्व पर भी जोर दिया। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद, बीमा में कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और व्यापक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन बनाना चाहिए।

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक चौराहे पर खड़ा है, जिसमें इसके वितरण प्रणालियों को बदलने की अपार संभावनाएं हैं। बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, तर्कसंगत नीतियां और हितधारकों के बीच बढ़ता सहयोग 2030 तक एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) जैसे स्वास्थ्य सेवा-विशिष्ट व्यवसाय ट्रस्टों के निर्माण जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र की सलाह देते हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा, 'अनुकूलित फंडिंग तंत्र नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और हमारी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर सकते हैं।'

यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं की तीव्र कमी को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता भी चाहता है। जबकि 70 फीसदी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है, 80

भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, गोपीनाथ बोलीं - 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए करने होंगे जतन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप-प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन, 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की विकासित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकास को और तेज करने के लिए पिछले दशक के मुकाबले कहीं अधिक बड़े संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी।

वे यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में बोल रही थीं। बैठक की शुरुआत दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम और दो अन्य को प्रतिष्ठित क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित करके की। व्यवसाय जागत के दिग्गजों, उद्योगपतियों, शिक्षा, कला और संस्कृति तक के क्षेत्रों के शीर्ष वैश्विक नेताओं के सबसे बड़े संगम में भाग लेने के लिए कई भारतीय नेता भी यहां पहुंचे हैं।

चीन अपनी समस्याओं का सामना कर रहा है
गोपीनाथ ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था 3.3 प्रतिशत की स्थिर गति से बढ़ रही है, लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद हैं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जबकि यूरोप चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन अपनी समस्याओं का सामना कर रहा है और उसे अपने संपत्ति क्षेत्र को संवोधित करने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इस मौके पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और सीईओ बोर्ज बेस ने कहा कि यह बैठक हमारे दौर के सबसे अनिश्चित क्षणों में हो रही है क्योंकि नई भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक और तकनीकी ताकतें हमारे समाजों को नया रूप दे रही हैं।

भारत में रोजगार बाजार को बढ़ावा देने की जरूरत

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगामी बजट में रोजगार बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का 85 के स्तर तक पहुंचना किसी घरेलू कारक की बजाय अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने की वजह से है। भारत छह प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जो वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन, जब हम प्रति व्यक्ति

आंकड़ों को देखते हैं तो इसे और अधिक तेजी से बढ़ने की जरूरत है।

निराशावाद या नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक एवं अध्यक्ष क्लास श्वाब ने कहा कि हमारे समाज पर भरोसा बहाल किया जाना चाहिए, जबकि निराशावाद और नकारात्मकता को व्यावहारिक कदमों से बदला जाना चाहिए। विश्व के नेता ऐसे समय में एक साथ आ रहे हैं, जब दुनिया गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। बेहतर भविष्य के लिए सहयोग जरूरी है।

दुनिया को तार्किक युग के लिए तैयार करने के लिए एक मजबूत वैश्विक साझेदारी भी नितांत आवश्यक है।

इस अवसर पर विश्व आर्थिक मंच ने भारत सहित 13 देशों के 15 संगठनों के 18 सामाजिक उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के लिए श्वाब फाउंडेशन पुरस्कारों की घोषणा की। अवंती फेलो के अक्षय सक्सेना, आरसीआरसी के वेद आर्य श्वाब फाउंडेशन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं।

दावोस के विश्व आर्थिक मंच पर भारतीय नेताओं का जमावड़ा

तेलंगाणा के मुख्यमंत्री ए रवंत रेड्डी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी इस वैश्विक आयोजन में शिरकत की है। नायडू ने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सही समय पर सही नेता मिला है और वह देश को विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मापदंडों पर शीर्ष पर ले जाएंगे। भारत मंडप, तेलंगाणा मंडप और 'स्वर्ण आंध्र 2047' आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

पासवान ने कहा कि भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय, श्रमिक नेतृत्व की भूमिकाओं सहित हर जगह अपनी योग्यता साबित करते हैं। सफलता की यह कहानी वैश्विक मंच पर और आगे बढ़ेगी। आधिकारिक उद्घाटन समारोह से कुछ समय पहले ग्रीनपीस कार्यकर्ताओं ने बैठक के मुख्य हॉल के बाहर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

घर खरीदारों को टैक्स के बोझ से मिलेगी राहत? क्या डिमांड कर रहा रियल एस्टेट सेक्टर

परिवहन विशेष न्यूज

बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। यह क्षेत्र खासतौर पर इंडस्ट्री का दर्जा और टैक्स से जुड़ी रियायतें चाहता है। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि टैक्स छूट मिलने से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे डिमांड में उछाल आएगा।

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। इसका असर सभी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। खासकर, रियल एस्टेट सेक्टर पर, जो देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसीलिए इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए खास उपाय करेंगी और टैक्स से जुड़े मोर्चे पर भी कुछ राहत देंगी। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं।

घर खरीदारों को मिले राहत
बैसिक होम लोन के फाउंडर और सीईओ अतुल मोगा का कहना है कि केंद्रीय बजट में होम लोन की EMI चुकाने वालों को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए- जैसे सेक्शन 80 सी के तहत। प्रिंसिपल रीपेमेंट में र 1.5 लाख के कैप को बढ़ाना और सेक्शन 24 बी के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट को बढ़ाना अच्छी पहल हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इससे घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल जैसे



रियल एस्टेट को बजट से क्या मिलेगा?

सीमेंट पर अभी 28 फीसदी टैक्स लगाया जाता है, इसमें कटौती कर लागत को काफी कम किया जा सकता है। इससे घर खरीदने वालों का सीधा फायदा होगा।

टैक्स का बोझ घटाने की मांग
निम्बस् थ्रूप के सीईओ साहिल अग्रवाल का भी मानना है कि घर खरीदने वालों को टैक्स में अधिक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'घर खरीदारों पर लगाए जाने वाले करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। यह कई राज्यों में संपत्ति के मूल्य का 12 फीसदी से अधिक है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की थी, लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। साथ ही, हम सरकार से रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स पर फिर से विचार करने और राहत देने की गुजारिश करते हैं।'

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का भी सुझाव है कि टैक्स छूट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी की कीमत और निर्माण लागत बढ़ी है। इसलिए होम लोन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करने से घर खरीदारों को काफी राहत मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने और जीएसटी इन्पुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सुधार भी मांग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।'

इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से बदलेगी सूरत
हाउसिंगडॉटकॉम और प्रॉपर्टाइगरडॉटकॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाला भी रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की वकालत करते हैं। उनका

कहना है, 'रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से इंडस्ट्री के दर्जे का इंतजार कर रही है। अगर इसे इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है, तो डेवलपर्स के लिए फंड जुटाना आसान हो जाएगा। इससे उन्हें बढ़ती इन्पुट और लैंड कॉस्ट के बीच उधारी खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।' अग्रवाला का कहना है कि जीएसटी दरों को सरल बनाना और इन्पुट टैक्स क्रेडिट तंत्र को सुव्यवस्थित करना भी अच्छी पहल हो सकती है। इससे खरीदारों के लिए आवास को अधिक सुलभ और किफायती बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते, नई ग्रीनफील्ड सिटी विकसित करने और मौजूदा शहरी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को लागू करना भी जरूरी है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, राँ जूट की बढ़ाई एमएसपी; जानें पूरी डिटेल्स



परिवहन विशेष न्यूज

कच्चे जूट की एमएसपी 2014-15 में 2400 रुपये प्रति विवटल थी। यह 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए 5650 रुपये प्रति विवटल हो गई है। इसका मतलब कि एक दशक के दौरान सरकार ने राँ जूट की एमएसपी 2.35 गुना बढ़ाई है। राँ जूट की एमएसपी बढ़ाने का असर जूट कंपनियों के शेयरों में भी दिख रहा है। Ludlow Jute के शेयरों में 4 फीसदी से अधिक का उछाल आया है।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उसने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए राँ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) 6 फीसदी यानी 315 रुपये बढ़ा दी है। अब किसानों को एक विवटल राँ जूट के बदले 5650 रुपये मिलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गायल ने मंत्रिमंडल की बैठक को बाद

यह जानकारी दी है। पीयूष गायल ने कहा कि नया एमएसपी अखिल भारतीय भारत और उत्तर प्रदेश उत्पादन लागत पर 66.8 फीसदी का रिटर्न सुनिश्चित करता है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। कच्चे जूट की एमएसपी 2014-15 में 2,400 रुपये प्रति विवटल थी। यह 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए 5,650 रुपये प्रति विवटल हो गई है। इसका मतलब है कि एक दशक के दौरान सरकार ने राँ जूट की एमएसपी 2.35 गुना बढ़ाई है। जूट कंपनी के शेयरों में एक्शन राँ जूट की एमएसपी बढ़ाने का असर जूट कंपनियों के शेयरों में भी दिख रहा है। Ludlow Jute & Specialties Ltd के शेयरों में 4 फीसदी से अधिक का उछाल आया है। यह एमएसए प्र 4.64 फीसदी उछाल के साथ 238.90 रुपये पर टूट कर रहा था। Cheviot Co Ltd भी जूट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसके शेयरों में भी 1 फीसदी से अधिक का उछाल आया है।

गंभीर चिंता का विषय: आत्महत्या करते छात्र

डॉ. सत्यवान सौरभ

वैसे तो इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से विचलित है, इनमें विशेषतः छात्र विचलन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हमारे देश में प्रति 100 में 15 से अधिक छात्र आत्महत्या से प्रभावित हो रहे हैं। वे अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों, बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। पारिवारिक दबाव, शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अवल आने की महत्वाकांक्षा ने छात्रों के एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। अभिभावकों के अपनों की उड़ान बन जाने वाले, परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को घर पर पिटाया पड़ता है। परीक्षा और नतीजों के दबाव में छात्रों की आत्महत्याएं अब आम घटनाएं बनती जा रही हैं। छात्र आत्महत्याओं में बेतहाशा वृद्धि के पीछे मानसिक तनाव सबसे आम कारक बन चुका है। तनावग्रस्त छात्रों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं, छात्रों का तनाव हद से गुजरने लगता है। पूरी युवा पीढ़ी का परीक्षा के दिनों में

ऐसे हालात से दो-चार होना देश और समाज, अभिभावकों और शिक्षाविदों, सभी के लिए अब गंभीर चिंता का विषय हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र में दशकों से व्याप्त कई बुनियादी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर अभी तक पार पाने में कठई कामयाब नहीं हो पा रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद से भारतीय छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और प्रदर्शन करने के लिए भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दबाव को संभालने, माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थता मनोवैज्ञानिक अकादमिक उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने अनाजाने में छात्रों के बीच तीव्र दबाव और प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर दिया है। शैक्षणिक उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ-साथ सामाजिक अपेक्षाओं और असफलता के डर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने चिंता, अवसाद और तनाव जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में वृद्धि में योगदान दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई बार छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का लगातार दबाव

रहा है। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आक्रामकतापूर्वक पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं। यह अंतर्निहित दबाव मानसिक परेशानी के विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें चिंता, विफलता का डर और कम आत्मसम्मान शामिल है। गंभीर मामलों में, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आत्म-नुकसान का कारण बन सकती हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या के प्रयासों के विचार को भी जन्म दे सकती हैं। प्रतियोगी पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इससे बच्चों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बच्चों के जीवन में तनाव के पौधों की बड़ी वजह यह भी है कि लंबे समय तक स्कूल के घंटों के बाद बच्चे घर लौटते ही होमवर्क निपटाने में जुट जाते हैं। इसके बाद ट्यूशन के लिए दौड़ पड़ते हैं। खाना-पीना, सोना, खेलकूद, सब हथाम हो जाता है। आराम करने और अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में छात्रों के लिए कम नॉट और अवसाद की स्थिति या गंभीर तनाव का सबब बन रही है। वर्तमान प्रतियोगी दौर में चिंता, अवसाद और तनाव जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में वृद्धि में योगदान दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई बार छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का लगातार दबाव



उत्कृष्टता की तुलना करना इस अवसाद के पीछे महत्वपूर्ण कारक है। भारत में किसी भी छात्र के साथ एक साधारण साक्षात्कार, चाहे वह जेईई, एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा कि छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। हर शिक्षक, हर रिश्तेदार कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के महत्त्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्कूल से स्नातक होने के बाद क्या करने की आकांक्षा रखता है, या जहाँ उसकी रुचियाँ हैं, उसके बारे में सहज पृष्ठदाख बहुत कम की जाती है।

इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग

सेंटर्स में दाखिला दिलाने का सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का भी सामना करना पड़ता है। जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते हैं कि र आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक

संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। ऐसे कठिन दौर में, आज छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा सिक्कन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा बोझ ही भरभरा कर गिर सकता है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है। परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। अभिभावकों का पूरा ध्यान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत की विफलताओं से सीखना और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

भोपाल: आईजी बंगला चौराहा पर पिछले 40 साल से मूत्रालय की कमी, व्यापारी और ग्राहकों को हो रही परेशानी

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल। सरकार द्वारा स्वक्षता अभियान के तहत शहरों को कचरा और गंदगी मुक्त करने के प्रयासों के बीच, राजधानी भोपाल के पुराने शहर आईजी बंगला चौराहा पर आज भी लोग मूत्रालय के लिए परेशान हैं।

यह स्थित 18 निजी अस्पतालों, 11 निजी सहित एक शासकीय स्कूल, एक शासकीय अस्पताल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, 22 कोचिंग संस्थानों, कई दुकानों और होटलों के साथ-साथ यहां आने-जाने वाले लोगों को अब कूलिंग कॉम्प्लेक्स या मूत्रालय की सुविधा नहीं मिली है। व्यापारी और स्थानीय लोग इस समस्या से खासी

परेशान हैं। बीते 35 वर्षों से चौराहे पर पान की दुकान चलाने वाले प्रेम नारायण ने बताया कि शेषाब करने के लिए कोई भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। पेशाब आने पर दुकान से बहुत दूर जाना पड़ता है और खुले में जाना पड़ता है। यह न केवल असुविधाजनक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

यहां आने वाले ग्राहक आम जन और व्यापारियों की मानें तो, खुले में पेशाब करने से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। साथ ही, यह भी एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है, क्योंकि दिनभर यहां बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं, जो इस स्थिति को अव्यवस्थित बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है।

स्थानीय समाजसेवियों और व्यापारियों ने इस समस्या को उठाते हुए कहा है कि भोपाल जैसे बड़े शहर में सुविधा जनक मूत्रालय की कमी बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिले।

इस मामले में समझदारी के साथ समाधान की आवश्यकता है ताकि शहर की सफाई और स्वास्थ्य को दिशा में उठाए गए कदम सफल हो सकें। प्रशासन को ये ध्यान में रखना होगा कि नागरिकों की बेसिक जरूरतों को पूरा किए बिना, स्वच्छता कार्यक्रमों का सफल होना कठिन होगा।

घर बैठे उतार देंगे चश्मा, बढ़ जाएगी आंखों की रोशनी

कमजोर आंखों की रोशनी और आंखों पर चढ़ा चश्मा अक्सर आपको परेशान करता ही होगा। बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने से अच्छा है घर बैठे ही ये उपाय अपना लें, जिनसे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और इन्हें नियमित रूप से करने से चश्मा भी उतर सकता है।

1. बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर उसे पीस लें। इस मिश्रण का 10 ग्राम हिस्सा 250 मिली दूध के साथ रात में सोने से पहले लें। 40 दिन तक लगातार इसे इस्तेमाल करने से आप महसूस करेंगे कि आंखों की रोशनी बढ़ी है। याद रहे इसे लेने के दो घंटे बाद तक पानी न पिएं।

2. आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होने से यह आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।



आंवला का सेवन पाउडर, कैप्सूल, जैम या जूस की तरह किया जा सकता है। हर सुबह शहद के साथ ताजा आमले का रस पीने से या रात में सोने से पहले लें। इसके साथ एक चम्मच आमला पाउडर खाने से भी फायदा मिलता है।

3. एक चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी में जाल कर रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह इस पानी को छान कर इसी से आंखें धुलें। साथ ही अगर आंखें धुलते वक्त मुंह में ताजा

पानी भरें रखेंगे तो और भी फायदा मिलेगा। एक ही महीने में आपको फर्क महसूस होगा।

4. गाजर में फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन की मात्रा काफी होती है जो इसे आंखों के लिए असरदार बनाते हैं। नियमित रूप से कच्ची गाजर को सलाद की तरह खा कर या उसका रस पी कर आप अपनी आंखों की रोशनी तेज कर सकते हैं।

5. बिलबेरी एक तरह का बेर है जो शरीर में खून के बहाव को बढ़ाता है। ताजी बिलबेरी खाने से रात में कम दिखने की बीमारी और कमजोर रोशनी की समस्या दूर हो जाती है।

6. याद रहे आपको खाने में सभी पोषक तत्व मौजूद हों। संतुलित आहार सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए जरूरी है। गाजर का रस, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, फल, मेवे, गोभी और नींबू इसका हिस्सा हो सकते हैं।

7. हरी घास पर सुबह सुबह नंगे पांव चलना आंखों को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें।

8. सुबह उठने पर अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो उन्हें अपनी आंखों पर रख कर सिकाई करें। ऐसा 4-5 बार करें तो आंखों को बहुत फायदा पहुंचेगा।

श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर एवं नंदिशाला का शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न

मेड़चल यल्मपेट स्थित श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड की प्रवासी संस्था के लोग श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान के माध्यम से श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास बुधवार 22 जनवरी विद्वान ब्रह्मणों के अनुसार कुम्भ लगन और शुभ मुहूर्त में प्रातः 8.34 से 10 बजे सम्पन्न हुआ है। जगदीश सीरवी द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित में चेयरमैन जयपाल सिंह नयाल सनातनी एवं शिलान्यास स्वागत समिति के अध्यक्ष राम भाटी ने बताया कि भाग्यनगर की पावन धरा पर श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा शिलान्यास व आरती व पुजा अर्चना कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि मल्कागरी सांसद ईटला राजेंद्र व कांग्रेस पूर्व विधायक हनुमंत राव व चेयरमैन, समस्त गणमान्य नेता व सर्व समाज गणमान्य पदाधिकारी रामजी भाटी, राजेश कुमार अग्रवाल, धनजी भाई पटेल, गोपाल अग्रवाल, जयदयाल, कोटी हनुमंत राव, चेनाराम सीरवी, राजेश परिहार, सोहनलाल हाम्बड़, मोतीलाल मादावत, भोलाराम पंवार, जयदयाल, जयराम, जगदीश परिहार, कानाराम, पाप्सा, समस्त हैदराबाद उत्तराखंड के समाज जन के माध्यम उत्तराखंड के प्रवासी बाल और वयस्क कलाकार द्वारा बहुत शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट एवं देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान द्वारा पधार भक्तों के लिए अल्पाहार प्रसादी की सुंदर व्यवस्था थी है। लाईव प्रसारण बी आर एस राजस्थानी चैनल ने भगवानराम राठीड किया है। पूजा-अर्चना के पश्चात् प्रसादी सभी भक्तों ने लाभ लिया। कवरेज पत्रकार जगदीश सीरवी द्वारा किया। समस्त श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट कमेटी व पंच श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर चेयरमैन जयपाल सिंह नयाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया।



देश पर मर मिटने वाला।

‘वह भारत का नायक, वीर सपूत वीर सैनानी आजादी का मतवाला, देश पर मर मिटने वाला।

जिसने कभी भी नहीं, झुकते दिया भारत का मान गांधी-नेहरु का साथ जिसने दिया, देश के दुश्मनों को सबक सिखाया देश पर मर मिटने वाला।

अपनी युवा फौज का वह नायक, आजाद हिंद का सैनानी बन जिसने युवाओं को हिन्दुस्तान से जोड़ा, देश पर मर मिटने वाला।

मातृभूमि की वंदना में तन-मन, देश को समर्पित करने वाला। आजादी की लड़ाई का वह वीर सैनानी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, देश पर मर मिटने वाला ॥ हरिहर सिंह चौहान



अर्थराइटिस

उभरने के साथ अक्सर लोगो को गठिया और जोड़ों का दर्द होने लगता है जो गठिया का लक्षण भी हो सकता है। गठिया की वजह यूरिक एसिड को माना जाता है, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर इसके कण घुटनों और अन्य जोड़ों में जमा होने लगते हैं जिस वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। कई बार ये दर्द इतना असहनीय होता है कि व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है। गठिया की बीमारी हो तो रात के समय जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और सुबह अकड़न होती है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो सही समय पर इसकी जांच करवाना जरूरी है, अगर ये गठिया का रोग है तो तुरंत इसका इलाज करना चाहिए वरना जोड़ों में दर्द से आराम मिलता है। इससे जोड़ों को नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए आप कुछ धरे लु उपचार कर आराम पा सकते हैं। आइए जानते हैं।

गठिया, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द के सरल घरेलू उपाय अखरोट एक महीने तक लगातार रात को 15 से 20 गिरे अखरोट की भिगो कर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। दो महीने लगातार इस उपाय को करने से गठिया का रोग जड़ से ठीक हो जाता है।

लहसुन और दूध दस कलियाँ लहसुन की 100 ग्राम पानी या दूध में मिला कर पीने से दर्द में जल्दी आराम मिलता है। बथुआ बथुआ के ताजा पत्तों का रस आधा कप सुबह शाम खाली पेट पीने से गठिया ठीक हो जाता है। इसके सेवन के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाने पिये नहीं। अमरूद की पत्तियाँ अमरूद की 4 से 5 नई कोमल पत्तियों को पीस लें और उसमें थोड़ा काला नमक मिला कर खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है।